श्री नरेन्द्र मोहन: महोदय, आप कृपा करके मंत्री जी को आदेश दीजिए पूरी जानकारी देने के लिए। मंत्री जी यह बता दें कि कितना नुकसान हुआ था और उसकी भरपाई हो पाई या नहीं हो पाई। अब फायदा हो रहा है या नहीं, यह बता दें?...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि नौ हजार करोड़ रुपया यहां आना था लेकिन इसमें से केवल 5500 करोड़ रुपया आया था। इस नये पैकेज के बाद 2700 करोड़ रुपया भी आया है। इसके अलावा मैंने कहा कि आप टोटल में पूछ रहे हैं तो टोटल में हमने ग्रोथ रेट बतला दिया।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: चेयरमैन साहब, एक मिनट।...(**व्यवधान**)... चेयरमैन साहब, माननीय मंत्री जी ने...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम: चेयरमैन साहब, एक साथ चार-चार सदस्य सवाल पूछ रहे हैं। एक बार में एक सदस्य सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा।...(**व्यवधान**)...

SHRI S. VIDUTHALAIVIRUMBI: Mr. Chairman, Sir, my question is clear. Making a call from one cellular telephone to another cellular telephone is different. Making a call from a cellular phone to a basic telephone is different. Making a call from a basic telephone to a cellular telephone is different. When a person makes a call from a cellular telephone to a basic telephone, the cellular company has to pay some amount to the Department of Telecommunications. In the same way, if a person makes a call from a basic telephone to a cellular telephone, the Department of Telecommunications has to pay some amount to the cellular company. I think, the percentage is not the same when a cellular company makes the payment to the Department of Telecommunications. Rather, it is a different percentage. If there is a different percentage, then, there is no level playing field. That is why I am putting this question.

श्री राम विलास पासवान: सर, आप तो जानते हैं कि हमारे यहां हर चीज का काम बंटा हुआ है। कुछ काम ट्राई के जिम्मे है, रेगुलेटर के जिम्मे है और इसको ट्राई फिक्स करता है। यह जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह ट्राई का है। इसको ट्राई फिक्स करता है हम नहीं करते हैं।...(**व्यवधान**)...

Concession to senior citizens by AI

*23. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 942 given in the Rajya Sabha on 1st August, 2000 and state:

(a) whether Government have taken steps to take up the matter of

"Concession to senior citizens by Air India" for consideration at the Tariff Coordination Conferences of International Air Transport Association;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (c) The issue of concession to senior citizens has not been taken up at the Tariff Coordinating Conference of International Air Transport Association (IATA) primarily due to the fact that various promotional fares exist with discounts ranging from 30-50% of the normal fares. Other airlines operating international services from India have no senior citizen fares. Senior citizens normally travel on a round trip basis.

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणेः माननीय सभापति जी, 'टैरिक कोआर्डिनेशन कांफ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन' की मीटिंग में इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। इतना ही नहीं, सामान्य किराये में 30 से 50 प्रतिशत की छूट दी है। इसके बारे में मंत्री महोदय ने साफ कहा है। मेरा सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन्स को, वरिष्ट नागरिकों को सुविधा देने के बारे में क्या इस मीटिंग में वहां पर सरकार की तरफ से विचार रखे गए थे? मैं जानना चाहता हूं कि वरिष्ट नागरिकों को ट्रेवलिंग में कुछ सुविधा देने के लिए एयर इंडिया की ओर से पहल करने में दिक्कत क्या है?

श्री शरद यादव: सभापति जी, दो तरह के फेयर्स होते हैं एक आईएटीए फेयर्स होते हैं और एक डीजीसीए के फेयर्स होते हैं। माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है कि जो टैरिफ कांफ्रेंस हुई थी उसमें हमारी तरफ से यह सवाल उठाया गया है या नहीं उठाया गया है। इस सवाल को हमारी तरफ से उठाया गया हो या न उठाया गया हो, लेकिन यह सवाल वहां पर उठा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ तय करने वाले जो लोग हैं उन्होंने आईएटीए में इस सवाल को उठाया है, उसमें इस बारे में चर्चा हुई है, लेकिन आम राय नहीं हो पाई है। माननीय सदस्य का यह कहना है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एयर इंडिया में प्रोमोशनल फेयर्स में कई तरह के कंसेशन दिए जाते हैं और जो एक्सकरशन फेयर्स हैं वह 40 परसेंट तक हो जाता है। यह एक तरह से एयर इंडिया में सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोग जो फेयर लेते हैं तकरीबन उसके बराबर होता है। यदि माननीय सदस्य उत्सुक हैं तो मैं यह जरूर सदन को बताना चाहता हूं कि इस पर हम विचार कर लेंगे और सीनियर सिटीजन्स को, चूंकि हम सभी तरह की केटेगरीज़ के लोगों को यह कंसेशन देते हैं, हम इस पर भी विचार कर लेंगे। यदि इसका हम पर कामर्शियली ज्यादा बर्डन नहीं आएगा तो हम इस मामले को दिखवा लेंगे और निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आयात में इसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि फेयर्स दो तरह के होते हैं और जो डी.जी.सी.ए. के फेयर्स होते हैं, वह

हर देश अपने तरीके से तय करता है। इसलिए इसको हम दिखवाने का काम कर लेंगे। और माननीय सदस्य की जो मंशा है, उसको देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Second question.

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: धन्यवाद महोदय।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, I refer to the reply which the hon. Minister has made to the main question. The third line from below states, "Other airlines operating international services from India have no senior citizen fares". I do not think we need to follow what the other airlines are doing. We have our own policies on many matters in Air India. Similarly, the answer says, "Senior citizens normally travel on a round trip basis". It amounts to saying that young citizens do not go on round trips. They also go on a round trip basis. So, this reply does not sound to be logical. Is it true that Government of India officers take their spouses free? It seems that is allowed by Air India. Then, why not senior citizens who can't travel alone? They need their spouses with them. If you have a special policy for Government officers, why don't you include senior citizens also in that policy?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं और मैंने स्वयं ही कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आयता है...जो आप कह रहे हैं, वह सिर्फ आफिसर वर्ग के लिए नहीं है, वह सब के लिए है, वह जनरलाइज़ है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: क्या जनरलाइज़ है? सर, मैं माफी चाहता हूं लेकिन मंत्री जी के पास इसकी इनफॉर्मेशन नहीं है। आप यह बताएं कि खाली गवर्नमेंट आफिसर्स के लिए कोई स्पैशल पॉलिसी है या नहीं? अगर है तो सीनियर सिटिज़न्स को भी उसमें ऐड कर दीजिए। हमने आपको कंसलटेटिव कमेटी में भी रिक्वैस्ट की थी कि एम.पीज़. को इसमें इनक्लूड कर दें। आपने उनको इनक्लूड नहीं किया। एम.पीज को छोड़ दीजिए लेकिन सीनियर सिटिज़न्स को तो इनक्लूड करिए।

श्री शरद यादव: आप जो कह रहे हैं वह बात वाजिब नहीं है। यह सिर्फ आफिसर्स वर्ग के लिए नहीं है, सबके लिए है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: क्या सबके लिए है?...(**व्यवधान**)...

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, कृपया यह उत्तर पूरा करवाइए।

श्री सभापति: उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दे दिया है।

श्री शरद यादव: यह स्कीम सबके लिए है, यही कह रहा हूं।...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन: सब में से किसके लिए है?...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव: जो ट्रैफिक जाता है, उनके लिए है, फर्स्ट क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए है।...(**व्यवधान**)...

DR, Y. LAKHSMI PRASAD: Buy one, get one free.

श्री शरद यादव: यह स्कीम सबके लिए है। फुल फेयर पेसेंजर्स के लिए कम्पनसेट स्कीम लागू है।

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया: सभापति महोदय, डोमैस्टिक एयरलाइन्स में और इंटरनेशनल एयरलाइन्स में विभिन्न विमान कंपनियां अपने कंसैश्नल रेट्स अनाउंस करती हैं और माइलेज पर, ट्रिप्स पर तरह तरह के रेट्स अनाउंस होते हैं। एयर इंडिया में और इंडियन एयरलाइन्स में सीनियर सिटिज़न्स को जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, क्या वे सारी की सारी सुविधाएं प्राइवेट एयरलाइन्स में भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी? दूसरा महोदय, दो तरह के पैसेंजर्स जाते हैं। आम लोग तो व्यापार करने जाते हैं और दूसरे ऑफिस अटैंड करने जाते हैं या मीटिंग अटैंड करने जाते हैं-जिनमें गवर्नमेंट इम्प्लाइज भी होते हैं और पार्लियामेंटेरियन लेजीस्लेटर होते हैं। पर इसके सिवाय इलाज कराने के लिए खासकर कैंसर और हॉर्ट के पेशेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, उनके लिए टैरिफ में, किराए में कटौती करना या उसके लिए कुछ एमाउंट एयरलाइंस की तरफ से फिक्स किया जाएगा जो कि प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेटर्स पर भी लागू होगा, क्या इसके बारे में मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कैंसर पेशेंट्स और दूसरी तरह के लोगों के बारे में, हमारी एयरलाइन्ज जो ऐसे कुछ स्पेशल केस आते हैं, उनके मामले में विचार करके उनको छूट देने का काम करती है लेकिन जो प्राइवेट एयरलाइन्स हैं, वे हमारे साथ में नहीं हैं। उनको हम फोर्स नहीं कर सकते। जो कमर्शियल एयरलाइन्स होती हैं, वे कमर्शियल बेसिस पर चलती हैं...(**व्यवधान**)...

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया: फोर्स तो बाद में करेंगे, पहले कोशिश तो करिए।

श्री दीपांकर मुखर्जी: यह आपको करना पड़ेगा...आपको कोशिश करनी पड़ेगी।

श्री शरद यादव: मैं आपसे कहना चाहता हूं कि...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: हम कोशिश करेंगे, ऐसा आप बोल दीजिए।

श्री शरद यादव: इस मामले में जो बात कही गई है, उस पर हम विचार करेंगे।

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया: महोदय, हर एयरलाइन्स में एयर होस्टेस डिब्बा पैसेंजर्स से चन्दा इकट्ठा करती हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो मेरी सिर्फ यह गुजारिश है कि मंत्री महोदय ने क्या कोई ऐसा उपराला किया? क्या कभी उनको कहा और उनका कभी नेगेटिव आन्सर था? यह दबाव देने की बात नहीं है। आपने कोई उपराला किया है या नहीं, वह बताने की कृपा करें।

श्री शरद यादव: अभी तक तो इस बात को नहीं देखा गया। माननीय सदस्य ने इस बात को रखा है तो हम इस पर विचार करेंगे। इस मामले को जो प्राइवेट एयरलाइन्स हैं, उनके साथ उठाने का काम करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Now, Q.No. 24.

IBA Report on VRS for Public Sector Bank Employees

*24. SHRIMATI VANGA GEETHA:†

SHRI K. RAMA MOHANA RAO:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Indian Banks' Association has submitted a report to Government seeking approval for implementation of two VRS Schemes by the public sector banks;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken to implement the recommendations of Indian Banks' Association panel to right size staff strength and cut retirement age to fifty-eight years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL):, (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and **(b)** Yes, Sir. A Committee comprising representatives of Indian Banks' Association (IBA), Public Sector Banks and Minsitry of Finance was set up in June, 2000 for making recommendations on all aspects of Human Resource Management in the Public Sector Banks. This Committee in its Interim Report recommended introduction of a Voluntary Retirement Scheme and a Scheme for Sabbatical. IBA sought Government's no objection to

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Vanga Geetha.